सफलता की कुंजी

अवसर सूर्य उदय की तरह होते है यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गवा देंगे

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

अनमोल विचार

उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाये

-स्वामी विवेकानंद

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 8 JANUARY TO 14 JANUARY 2020 • VOLUME-20 • PAGES-4 • RATE-3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

बल्टन पार्क इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम की दयनीय हालत के लिए कौन है जिम्मेवार ?

लोकल बॉडी विभाग

■ जालंधर से नीरज की विशेष रिपोर्ट

जालंधर शहर विश्व स्तर पर कई चीजों के लिए पहचान रखता है जिसमें प्रमुखता एशीया स्तर जहां सब से ज्यादा अस्पतालों का होना और इन्टरनैश्नल लैवल का स्पोटर्स उद्योग का होना। इन दोनों के साथ-साथ यहां पर एक इन्टरनैश्नल स्टेडियम जिसको बल्टन पार्क के नाम से जाना जाता है। इस इन्टरनैश्नल क्रिकेट स्टेडियम में खेल-खेल कर कई महान खिलाडियों ने विश्व स्तर पर खेल के मैदान में लोहा मनवाया जिसमें प्रमुख खिलाडी हरभजन सिंह, राहुल शर्मा, मनदीप सिंह परन्तु इतने बड़े और महान खिलाडी देश को देने वाला स्टेडियम को भी राजनीतिक बली का शिकार होना पड़ा। पिछली अकाली-भाजपा सरकार के कार्यालय में यहां की डिस्ट्रीक क्रिकेट एसोसिशन का एक पद अधिकारी राजनीति में प्रवेश कर गया और उसको पहली सब से महत्वपूर्ण पोस्ट देकर नवाजा गया अपनी पदवीं को संभालने के बाद उसके द्वारा एक ऐसा बचकाना काम कर दिया जिसका परिणाम आज भी जालंधर के क्रिकेट प्रेमी युवाओं को दर्द देता है। इस राजनेता द्वारा इस स्टेडियम का नवीनीकरण करने के लिए अपने स्तर पर स्पोर्ट्स हब की तजवीज को सरकार को भेजा वो तो एक सराहनीय कदम परन्तु इस राजनेता द्वारा जो बचकाना और निदनीय काम किया गया वो यह है कि इसने इस प्रोजैक्ट से विकास के लिए जो धनराशि चाहिए उसके इतंजाम किये बगैर पुराने स्टेडियम को गिरा दिया जिसके परिणामस्वरूप वहां पर रह रहे ग्राउंडसमैन जो यहां इस स्टेडियम की दिन-रात देखभाल करते उनके सिर से छत छीन कर उनको इतनी भीषण सर्दी हो या गर्मी में तिरपाल की झुग्गियां बना कर रहने पर मजबूर कर दिया आज तक यह प्रोजेक्ट लंबित चला आ रहा है और पिछले दिनों अखबारों के माध्यम से फिर सुनने में मिला है कि इस स्पोर्ट्स हब को स्मार्टसिटी प्रोजेक्ट के तहत शामिल कर लिया गया है और इसके टैंडर प्रकिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी परन्तु इससे भी गंभीर मुद्दा यह है कि इस स्टेडियम की दयनीय हालत किसने की यह एक जांच का विषय है कि इसको तोड़ने का ठेका किस प्रावधान के अधीन और किन हालातों में किस को दिया गया यहां पर चल रहे डिस्ट्रीक क्रिकेट एसोसियशन किस की देखरेख में चल रही है कौन से पद अधिकारी यहां से अपने निजी हितों को पूरा करके शहर के प्रसिद्ध स्टेडियम को खंडर बनाने में लगे हुए इस स्टेडियम में जो लोकल जालंधर के क्रिकेट कल्ब या प्रोफैश्नल एसोसिशन द्वारा खेलने के लिए जो शुल्क दिया जाता है वो किसके द्वारा वसूला जाता है और इसमें खेलने के लिए एसोसिशन द्वारा क्या बुकिंग प्रकिया है या इसको किसी क्लब को पक्के तौर पर किसी पद अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुउपयोग करके किसी के साथ अपने स्तर पर तो नहीं करार कर लिया गया यह सब जांच का विषय है कि 12 से 15 लाख की अबादी वाले शहर जिसमें तकरीबन 50 प्रतिशत युवा पीढ़ी है जिनके ना तो एसोसिशन द्वारा कोई ग्राऊंड का इंतजाम किया गया और जो थी इसको अपने राजनीतिक भविष्य को चमकाने में उसकी बली ले ली। भाई भतीजावाद की राजनीतिक के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार ठहराने वाली भारतीय जनता पार्टी क्रिकेट बोर्ड के उच्चे पदों पर एक ही परिवार से सभी पद अधिकारी हिन्दोस्तान में परिवारवाद के बढ़ावा ना देने वाले दावों को किसी स्तर पर लागू करने में असमर्थ दिख रही है।

भाजपा केन्द्रीय मंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन की उड़ रही है धज्जियां

पुड्डा विभाग

■ जालंधर से विजय कुमार की विशेष रिपोर्ट

कपूरथला की प्रशासनिक क्यूं राष्ट्र की प्रतिष्ठा से अवगत नहीं समाचार पत्र द्वारा बार-बार स्चेत करने पर भी अचेतावस्था से जागृत नहीं हो पा रहा है एक निजी प्रतिष्ठत यूनिवर्सिटी जो जालंधर-फगवाड़ा राजमार्ग पर स्थित है और कपूरथला प्रशासनिक अधिकारी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती है, स्वच्छता की दयनीय व्यवस्था, ट्रैफिक की बदतर हालत, जगह-जगह पर दुकानदारों, आटो चालकों द्वारा, रेहड़ी वालों तथा यूनिवर्सिटी द्वारा भी (अतिक्रमण) नाजायज ढंग से कब्जाई गई सड़क एवं गंदे पानी के निकास एवं खाद्य पदार्थों के दूषित होने पर भी बिक्री पर न तो कपूरथला के स्वास्थ्य अधिकारी न ही ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक और न ही पुड़ा प्रशासन कपूरथला अथवा फगवाड़ा नगर पालिका के अधिकारियों पर तनिक भी प्रभाव दिखाई दिया है।

भिखारी एवं आटो चालकों द्वारा जगह-जगह रेहड़ी वालों द्वारा फैंके गए कूड़े ओवरब्रिज पर फैंके कूड़ा कर्कट एवं यूनिवर्सिटी द्वारा सफाई भी व्यवस्था न किए जाने परिणामस्वरूप देश-विदेश से शिक्षा ग्रहण करने आने वालों पर पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार की छवि धूमिल हो रही है विदेशों में माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाता यूनिवर्सिटी प्रबंधन और जिला प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारी उत्तदायी है दूषित खाद्य पदार्थों की वितरण प्रणाली से अगर कोई देश का या विदेश का विद्यार्थी बिमारी का शिकार होता है तो कपूरथला चिकित्सा अधिकारी व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे।

तय हुई निर्भया के गुनहगारों की मौत की तारीख, 22 जनवरी सुबह 7 बजे दी जाएगी फांसी

निर्भया मामले में आखिरकार फैसला आ गया है और पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों के डेथ वॉरंट को मंजूरी दे दी है। एडिशनल सेशन जेज सतीश कुमार अरोड़ा के सामने इस अहम मामले पर फैसला देने की जिम्मेदारी थी।

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

देश को स्तब्ध कर देने वाले निर्भया कांड के दोषियों के लिए सजा पर आखिरकार मुहर लग गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों के डेथ वॉरंट को मंजूरी दे दी है और तिहाड़ जेल में 22 जनवरी सुबह 7 बजे उन सब को फांसी दी जाएगी। दोषियों को सभी विकल्पों के इस्तेमाल के लिए 14 दिनों का वक्त दिया गया है। एडिशनल सेशन जेज

सतीश कुमार अरोड़ा के सामने इस अहम मामले पर फैसला देने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आज चारों दोषियों पवन शर्मा, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय का पक्ष सुना। सुनवाई के दौरान जज ने चारों दोषियों से पूछा कि क्या आपको जेल की तरफ से नोटिस मिल गया है? दोषियों ने कहा कि हां नोटिस मिल गया है और हमने उसका जवाब भी दिया और जो भी कानूनी विकल्प है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे. इससे पहले निर्भया मामले की सुनवाई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पूरी हो गई थी। बता दें कि 13 सितंबर 2013 को निचली अदालत ने निर्भया कांड के चारों दोषियों पवन शर्मा, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय को मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट निर्भया दोषियों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2018 में ही खारिज कर चुका है और इनके पास क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए डेढ़ साल का वक्त था लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से चारों दोषियों को नोटिस जारी कर उनके पास मौजूद विकल्प पर उनका जवाब लेने को कहा था।

अंकित

जब तक आप अपने समय की कद्र नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। समय का हर एक पल कीमती होता है। यह बात जानते सब हैं, लेकिन मानते कम ही लोग हैं।

■ पाब्लो पिकासो

www.jalandharbreeze.com

साप्ताहिक

• साप्ताहिक 8 जनवरी 2019 से 14 जनवरी 2020

जालंधर ब्रीज

दखल

साइबर अपराध रोकने की चुनौती

पिछले एक दशक में भारत में साइबर अपराध 88 गुना बढ़े हैं। साइबर अपराधों के मामले में गिरफ्तारी में भी दस गुना बढ़ोतरी हुई है। साइबर अपराध के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। आज भारत की बड़ी आबादी डिजिटल जिंदगी जी रही है। अधिकांश लोग बैंक खाते से लेकर निजी गोपनीय जानकारी तक कंप्यूटर और मोबाइल फोन में रखने लगे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में अभी भी साइबर अपराध गैर जमानती नहीं है।

देश के 61 फीसद कारोबारी व अन्य श्रेणी के संस्थानों का विकास साइबर हमले से बुरी तरह प्रभावित है। इस वजह से इन संस्थानों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यह खुलासा एक आईटी विश्लेषक कंपनी ने किया है। यह स्थिति इस बात को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि देश के 95 फीसद कारोबारी और संस्थान डिजिटलीकरण की राह पर तो चल दिए हैं, लेकिन साइबर हमले से निपटने के लिए पुख्ता सुरक्षा तंत्र विकसित नहीं कर पाए हैं। आंकड़े बताते हैं कि दो वर्षों के दौरान 46 फीसद संगठनों ने साइबर हमले झेले हैं। 20 फीसद संगठनों ने तो बीते एक वर्ष में कभी भी साइबर हमले से बचने का मूल्यांकन तक नहीं करवाया। 70 फीसद संगठनों ने साइबर सुरक्षा को लेकर बचाव का रास्ता अख्तियार किया। सिर्फ 18 फीसद कंपनियों ने ही डिजिटलीकरण के शुरुआती चरण में साइबर सुरक्षा की व्यवस्था की। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में साइबर अपराध बीते दो वर्ष में दोगुना हो चुका है।

2015 में साइबर अपराध के 11592 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2017 में यह संख्या 21796 पहुंच चुकी है। यानी तकरीबन 88 फीसद की वृद्धि हुई है। इनमें बड़ी संख्या संस्थानों और संगठनों पर हुए साइबर हमलों, वेबसाइट हैकिंग और अवैध लेन-देन की है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड साइबर हमले को नाकाम करने के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने और साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने की दीर्घकालीन रणनीति तैयार करने की बात कह चुका है। लेकिन साइबर हमले कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। इससे संस्थानों, संगठनों व विशेषकर बैंकों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ी है। पिछले साल अमेरिकी कंपनी एफआईएस द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि देश के 18 से 36 वर्ष के आयु वर्ग के युवा उपभोक्ता बैंकों की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। उसका कारण यह है कि भारतीय बैंक अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बैंकों के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराध रोकने की है। लेकिन बैंक इसमें नाकाम रहे हैं। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले तीन वित्त वर्ष में बैंकों से जुड़े साइबर अपराध के 43204 मामले सामने आए हैं जिसमें अपराधियों ने 232.32 करोड़ रुपए का चूना लगाया है।

2014-15 में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े साइबर अपराध के 13,083 मामले सामने आए जिनमें 80.64 करोड़ रुपए की चपत लगी। इसी तरह वित्त वर्ष 2015-16 में मामलों की संख्या बढ़ कर 16 हजार 468 तक पहुंच गई। पिछले वित्त वर्ष में कुल 13,653 मामले सामने आए जिनमें 72.68 करोड़ रुपए की चपत लगी। साइबर अपराधियों के निशाने पर सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक देश में आइटी एक्ट के तहत पंजीकृत साइबर अपराधों के मामले में 2011 से अब तक तकरीबन 300 फीसद तक की वृद्धि हो चुकी है। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर साइबर अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो साइबर हमलावर न्यूक्लियर प्लांट, रेलवे, परिवहन और अस्पतालों जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर हमले कर सकते हैं जिससे कई गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती है और जनजीवन व सारे काम ठप पड़ सकते हैं। कुछ साल पहले भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में हैकरों ने साइबर हमला बोल कई देशों की सरकारों की नींद उड़ा दी थी। पिछले एक दशक में भारत में साइबर अपराध 88 गुना बढ़े हैं। साइबर अपराधों के मामले में गिरफ्तारी में भी दस गुना बढ़ोतरी हुई है। साइबर अपराध के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। आज भारत की बड़ी आबादी डिजिटल जिंदगी जी रही है। अधिकांश लोग बैंक खाते से लेकर निजी गोपनीय जानकारी तक कंप्यूटर और मोबाइल फोन में रखने लगे हैं।

इंटरनेट उपयोग करने के मामले में दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इंटरनेट पर जिस तेजी से निर्भरता बढ़ी है, उतने ही ज्यादा खतरे भी बढ़े हैं। यही वजह है कि हैकिंग की वारदातें भी तेजी से बढ़ रही हैं। भारत की ही बात करें तो यहां ऐसी अनेक देशी-विदेशी कंपनियां हैं जो इंटरनेट आधारित कारोबार और सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उचित होगा कि भारत सरकार ऐसी कंपनियों पर निगरानी रखने के लिए ऐसा निगरानी तंत्र विकसित करे जो इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखे। उचित यह भी होगा कि जिन कंपनियों की कार्यप्रणाली संदिग्ध नजर आए उन पर शिकंजा कस कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी कंपनियों के लाइसेंस निरस्त किया जाएं जो साइबर सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करने में कोताही बरत रही हैं। इसके अलावा देश में अनेक ऐसी विदेशी कंपनियां सेवाएं दे रही हैं जिनका सर्वर भारत में नहीं है। ऐसी कंपनियों को निगरानी की जद में रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि भारत में साइबर अपराध रोकने के लिए कानून नहीं हैं। भारत में साइबर अपराध को तीन मुख्य अधिनियमों के अंतर्गत रखा गया है। ये अधिनियम हैं-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और राज्य स्तरीय कानून।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मामलों में कंप्यूटर स्त्रोत और दस्तावेजों से छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग, आंकड़ों में हेराफेरी, अश्लील सामग्री का प्रकाशन, गोपनीयता को भंग करना जैसे कई अपराध शामिल हैं। भारत में साइबर अपराध के मामलों में सूचना तकनीक कानून, 2000 और सूचना तकनीक संशोधन कानून, 2008 लागू होते हैं। किंतु इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता, कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और जरूरत पड़ने पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। साइबर अपराध के बदलते तरीकों और घटनाओं ने भीषण समस्या का रूप ले लिया है। जुर्म की दुनिया में अपराधी हमेशा कानून को गुमराह करने के लिए नए-नए तरीके ईजाद करते रहते हैं। हैकिंग के जरिए रक्षा-सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियों में सेंध लगाने की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं।

सीबीआई भी साइबर हमले की चपेट में है। साइबर अपराधियों के बढ़ते हौसले की मुख्य वजह यह है कि देश में साइबर अपराधों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए कठोर तथा प्रभावी कानूनों का अभाव है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में अभी भी साइबर अपराध गैर जमानती नहीं है। इसलिए अधिकतम सजा तीन साल है। ये उचित होगा कि सरकार साइबर अपराध से जुड़े कानूनों में फेरबदल कर इसे कठोर बनाए और सजा की मियाद बढ़ाए। देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर थानों की संख्या में वृद्धि करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर शहरों में तो साइबर अपराध की शिकायत भी सामान्य थानों में कराई जाती है। देश में साइबर थानों की संख्या 50 से भी कम है। सरकार को साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून तो बनाना ही होंगे, आमजन को भी साइबर सुरक्षा से जुड़े उपायों का पालन करना होगा। मसलन हार्डड्राइव को सुरक्षित रखने के अलावा सिम्पल या वाट्सअप से संदेश भेजने पर जोर देना चाहिए। ईमेल पर दोहरी सुरक्षा कैसे हो इसका उपाय ढूंढना चाहिए। असुरक्षित वेबसाइट पर जाने से बचना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि तमाम हिदायतों के बावजूद साइबर सुरक्षा संबंधी उपायों का पालन नहीं हो रहा। साइबर अपराधियों के बढ़ते हौसले की मुख्य वजह यह है कि अपराधों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए कठोर तथा प्रभावी कानूनों का अभाव है।

■ अरविंद कुमार सिंह
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

रोका जाए जेएनयू का गुस्सा

जेएनयू में रविवार शाम हिंसा के विरोध में देशभर के छात्रों में नाराजगी है। इस गुस्से को बड़ा होने से रोकना सभी की जिम्मेदारी है। शिक्षा संस्थानों में इस तरह की हरकतों की कोई जगह नहीं है। इससे उन छात्रों पर खराब असर पड़ता है, जो वाकई में पढ़ने आए हैं।

जेएनयू में रविवार शाम को बड़ी हिंसा हुई। लाठी-डंडे, हॉकी स्टिक से लैस नकाबपोश हमलावरों ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और टीचरों को बेरहमी से पीटा। इसमें 25 से ज्यादा छात्र-टीचर घायल हो गए। यह घटना बताती है कि देश के शिक्षक संस्थानों में सुरक्षा का क्या हाल है। आए दिन कॉलेज में मारपीट, हॉस्टलों में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। प्रशासन तमाशा देख रहा है। आज जिस जेएनयू हिंसा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है, उसमें जेएनयू प्रशासन की तरफ किसी की नजर नहीं है। आखिर क्यों। कॉलेज परिसर में नकाबपोश लोग अगर घुसे तो यह पुलिस की नाकामी नहीं, जेएनयू प्रशासन की है। दिल्ली पुलिस की गलती यह है कि वह समय पर नहीं पहुंची। अगर जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आती तो शायद बवाल इतना बड़ा नहीं होता और बदमाशों को पकड़ लिया जाता। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में खुलेआम घूमते और तोड़फोड़ करते नकाबपोशों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये लोग दिन में डंडे लेकर घूमते दिखे। लेकिन ये नकाबपोश कौन थे और कहां से आए थे जवाब पुलिस और जेएनयू को देना होगा।

सवाल फिर वही कि जेएनयू प्रशासन क्या कर रहा था। जेएनयू के गेटों पर कड़ी सुरक्षा रहती है, कोई भी बाहरी शख्स कैंपस में आसानी से दाखिल नहीं हो सकता है। छात्रों को भी आई कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश मिलता है। अगर ये लोग बाहरी थे तो इतनी बड़ी तादाद में लाठी-डंडों और रॉडों के साथ कैसे और कहां से यूनिवर्सिटी में घुस आए। इसका जवाब यूनिवर्सिटी प्रशासन को देना ही होगा। इतनी देर तक कैंपस के अंदर हंगामा और स्टूडेंट्स के साथ मारपीट होती रही, इस दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कर रहा था। खासतौर से कैंपस में बड़ी तादाद में गार्ड्स तैनात रहते हैं, वे सब इस दौरान क्या कर रहे थे। उन्होंने हमलावरों को रोकने या पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। बहरहाल, जेएनयू में हुई हिंसा में छात्रसंघ अध्यक्ष आईशी घोष समेत 25 से ज्यादा छात्र और टीचर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें एम्स और सफदरजंग में भर्ती कराया गया। घटना के 17 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हो पाई, मगर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने हिंसा के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं, भाजपा ने इस मामले में राजनीति न करने की सलाह दी है।

पुलिस कह रही है कि नकाबपोश युवकों की पहचान हो चुकी है, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्लनी के उप-राज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट मांगी है। जेएनयू में रविवार शाम हिंसा के विरोध में देशभर के छात्रों में नाराजगी है। इस गुस्से को बड़ा होने से रोकना सभी की जिम्मेदारी है। शिक्षा संस्थानों में इस तरह की हरकतों की कोई जगह नहीं है। इससे उन छात्रों के मन पर खराब असर पड़ता है, जो वाकई में जेएनयू में पढ़ने के लिए आए हैं।

धुंध में उड़ान की सीमाएं

हर वर्ष सर्दी के मौसम में धुंध और कोहरे के शिकार बन जाने वाले उत्तर भारतीय विमानपत्तनों पर अब लगातार रडार और आईएलएस जैसे आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उपलब्ध कराने के इंतजाम किए जा रहे हैं। कंपनियों को भी पायलट को आईएलएस का प्रशिक्षण देने में लगभग दस लाख रुपए का खर्च आता है और जारी रहने वाले प्रशिक्षण में सभी पायलटों को अभ्यास देते रहने का अर्थ है करोड़ों का खर्च।

कोहरे के कारण जब विमानों को अपने लक्षित हवाई अड्डे की जगह कहीं और मोड़ दिया जाता है, तब भी कंपनी को घाटा उठाना पड़ता है। इसीलिए लक्षित हवाई अड्डे पर मौसम खराब होने पर कंपनियां उड़ानों में देर करती जाती हैं, जबकि इस स्थिति से अनजान यात्री अपने गंतव्य वाले हवाई अड्डे के मौसम को सुधरते देखकर यह नहीं समझ पाते कि उनकी उड़ान बार-बार देरी से होने और इस देरी के बढ़ते चले जाने का असली कारण आर्थिक है, तकनीकी नहीं। संतोष का विषय है कि हर वर्ष सर्दी के मौसम में धुंध और कोहरे के शिकार बन जाने वाले उत्तर भारतीय विमानपत्तनों पर लगातार रडार व आईएलएस जैसे आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उपलब्ध कराने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सर्दियों में धुंध और कोहरे के कारण नागरिक विमान सेवाओं के ठप हो जाने से परेशान हवाई यात्रियों के मन में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि चंद्रमा और मंगल ग्रह तक यान भेजने की तैयारी करने वाले भारत में अभी तक ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध हो सकी हैं जो हर साल लाखों यात्रियों को होने वाली इस मौसमी असुविधा का समुचित समाधान कर सकें।

इस संदर्भ में नागरिक विमानन सेवाओं के प्रति कोई धारणा बना लेने से पहले यह जरूरी है कि हवाई यात्रियों को दृश्यहीनता के वातावरण में उड़ान भरने की समस्या के हर पहलू की जानकारी हो। इस सच्चाई से अधिकांश यात्री अनभिज्ञ होते हैं कि अभी तक ऐसा कोई हवाई अड्डा विश्व में नहीं है जहां शून्य दृश्यता में भारी यात्री विमानों के उतरने की सुविधा हो। हां, यह जरूर है कि शून्य दृश्यता के बहुत नजदीक पहुंच जाने तक यह संभव है। हवाई पट्टी धरातल से सौ मीटर तक की ऊंचाई तक और रनवे विजुअल रेंज (वह क्षैतिज दूरी जहां से उतरने के लिए विमान को हवाई पट्टी की शुरुआत पर लगे चिह्न और सेंटर लाइन दिखाई देने लगते हैं) कम से कम पचास फीट होने तक विमान का उतरना और उड़ान भरना संभव हो सके। ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने वाले उपकरण का नाम है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। यह उपकरण हवाई पट्टी के बीचों-बीच एक रेडियो बीम उपलब्ध कराता है, जिसकी सीध में विमान की नाक बनाए रख कर पायलट विमान को पट्टी पर उतारता है।

इस प्रणाली का दूसरा अंग धरातल से एक कोण पर उठती हुई रेडियो बीम होती है, जिसकी मिसाल बच्चों के फिसलने के लिए बनाई गई फिसल पट्टी से दी जा सकती है। इस रेडियो बीम के साथ-साथ चलते हुए विमान को ऊंचाई से नीचे तक लाया जा सकता है। कॉकपिट में पायलट इन दोनों रेडियो बीमों से विमान की आड़ी और खड़ी दूरी एक डायल पर देख कर विमान की दिशा और उतरने की गति में आवश्यक सुधार करता चलता है, साथ ही उसके कानों में इस उपकरण से निर्देश चुनी हुई भाषा में मिलता जाता है। इनकी सहायता से विमान इतनी नीचाई तक उतारा जा सकता है, जहां से हवाई पट्टी को अपनी आंखों से देख कर पायलट लैंडिंग पूरी कर सके।

आईएलएस उपकरण तीन श्रेणियों के होते हैं। प्रथम श्रेणी अर्थात कैट वन आइएलएस की सहायता से विमान 200 फीट की ऊंचाई तक उतारा जा सकता है और उसके बाद उतरने के लिए सामने की दृश्यता कम से कम साढ़े पांच सौ मीटर तक होनी चाहिए, जहां से पायलट आंखों का इस्तेमाल करके ही विमान नीचे उतारता है। कैट टू में सौ फीट ऊंचाई और साढ़े तीन सौ मीटर रनवे विजुअल रेंज की सीमा होती है। कैट थ्री सिस्टम तीन तरह के होते हैं- 3 ए में कम से कम पचास फीट ऊंचाई और 200 मीटर की दृश्यता की सीमा होती है। कैट 3 बी सिस्टम में कम से कम पचास मीटर की दृश्यता चाहिए। अब रहा कैट 3 सी सिस्टम। सैद्धांतिक रूप से तो इसमें न्यूनतम ऊंचाई और दृश्यता की नहीं होती, लेकिन शून्य दृश्यता और शून्य ऊंचाई अर्थात रनवे पर विमान के छूने तक विमान को कैट 3 सी उपकरणों की सहायता से उतार लेने में समर्थ कोई सिस्टम न्यूयार्क के केनेडी हवाई अड्डे और लंदन के हीथ्रो के अलावा कहीं और नहीं हैं। ऐसे में पूरी दृश्यहीनता में उड़ान भरना केवल एक परिकल्पना है असलियत नहीं।

यह ध्यान में रखना होगा कि केवल हवाई अड्डे पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देने से ही आईएलएस का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता। इस सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए विमानों के अंदर भी समान उपकरण का होना अनिवार्य है। इस उपकरण का पूरा उपयोग करने के लिए पायलटों का प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक है। फिर प्रशिक्षण भी एक बार देने से काम नहीं चलेगा, पायलटों को इस उपकरण का इस्तेमाल करने का अभ्यास भी चाहिए। इतना सब होने के बाद श्रेष्ठतम आइएलएस से भी विमानपत्तन में उतरने के बिंदु तक जहाज ले जाने और फिर पार्किंग-बे तक जहाज को ले जाने में किसी तरह की मदद नहीं मिलती है। इस दौरान विमान की किसी अन्य विमान से या अन्य किसी चीज से टकरा कर हो जाने वाले हादसे में विमान के पायलट को कभी माफ नहीं किया जाता।

नतीजा यह होता है कि धुंध में जहाज को टैक्सी करते समय पायलट बेहद चौकन्ने रहते हैं। नतीजतन विमानों द्वारा जमीन पर बिताया गया समय धुंध में अपेक्षाकृत काफी बढ़ जाता है। इस कारण उड़ानों के बीच का अंतराल बढ़ता चला जाता है। इंजन चालू करके जहाज को टैक्सी करने की अपेक्षा उन्हें ट्रैक्टर या टग से जमीन पर टेक ऑफ बिंदु तक ले जाने से ईंधन की काफी बचत होती है, लेकिन आज के विशालकाय विमानों को टग करने वाले विशालकाय ट्रैक्टर भी कोहरे के कारण बहुत धीमी गति से चलाए जाते हैं। अतः इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम उच्चतम श्रेणी का होने के बावजूद धुंध और कोहरे में उड़ानों का सुचारू रूप से संपन्न होना कठिन हो जाता है। इस सब के चलते उड़ानों में देर होती चली जाती है।

संतोष का विषय है कि हर वर्ष सर्दी के मौसम में धुंध और कोहरे के शिकार बन जाने वाले उत्तर भारतीय विमानपत्तनों पर लगातार रडार और आईएलएस जैसे आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उपलब्ध कराने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पिछले दो-एक वर्षों में कोलकता का नेताजी सुभाष हवाई अड्डा भारत का पांचवां ऐसा विमानपत्तन बन गया है जहां पर अमृतसर, जयपुर, लखनऊ और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की तरह बहुत कम दृश्यता में विमानों के उड़ान भरने और उतर सकने के लिए आईएलएस कैट-3 बी उपलब्ध कराया गया है, बावजूद इसके कि ऐसी हर प्रणाली को स्थापित करने के लिए लगभग दस करोड़ रुपए खर्च होते हैं और उनका मासिक रख रखाव लगभग पचास लाख रुपए पड़ जाता है।

कंपनियों को भी पायलट को आईएलएस का प्रशिक्षण देने में लगभग दस लाख रुपए का खर्च आता है और जारी रहने वाले प्रशिक्षण में सभी पायलटों को अभ्यास देते रहने का अर्थ है करोड़ों का खर्च। जब सभी देशों में एअरलाइंस चलाना बेहद घाटे का सौदा साबित हो चुका है, तब भारत की कितनी विमान कंपनियां सारे विमान चालकों के प्रशिक्षण पर इतना धन सहर्ष करना चाहेंगी? कोहरे आदि के कारण जब विमानों को अपने लक्षित हवाई अड्डे की जगह कहीं और मोड़ दिया जाता है, तब भी कंपनी को घाटा उठाना पड़ता है।

■ राकेश पांडेय
(वरिष्ठ पत्रकार)

ई-गवर्नेंस सिस्टम से बेहतर हुई परिवहन व्यवस्था

प्रदेश में यातायात और पविहन व्यवस्था को सुदृढ़ और जनोपयोगी बनाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में ई-गवर्नेंस सिस्टम लागू किया। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी, अवैध परिवहन पर नियंत्रण और परिवहन विभाग की कार्य-प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव नजर आने लगा है इस नवाचार के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली में कसावट लाकर राजस्व को भी बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप पिछले साल परिवहन राजस्व संग्रहण में करीब 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 में माह नवंबर तक 1782 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ और वर्ष 2019-20 में नवंबर माह तक 1918.14 करोड़ परिवहन राजस्व संग्रहण हुआ। बकाया राजस्व की वसूली के लिए 5 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम आयु वाले परिवहन वाहनों को क्रमबद्ध तरीके से छूट प्रदान की गई। राज्य सरकार ने वचन पत्र के अनुसार बीते एक वर्ष में महाविद्यालयी छात्राओं को 65 हजार निःशुल्क ड्रायविंग लायसेंस वितरित किए। दिव्यांग हितेषी मानकों के अनुरूप जून में परिवहन विभाग की नई वेबसाइट लांच कर उसे लाइव किया गया। महिलाओं को निःशुल्क एक लाख 11 हजार 898 लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए, जो गत वर्ष जारी लाइसेंस की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक थे। प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म-दिवस 19 नवंबर से प्रियदर्शिनी दिवस पर महिलाओं के लिए एक साल तक निश्चित अवधि के अंतर से त्रैमासिक निःशुल्क शिविर लगाने का निर्णय ले कर उसका क्रियान्वयन शुरू किया गया।

प्रदेश में पीपीपी मोड पर ऑटोमेटेड ड्रायविंग टेस्टिंग ट्रेक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसे परियोजना का स्वरूप दिया गया। इसके संचालन के लिए सीआईआरटी को तकनीकी कंसलटेंट नियुक्त कर परियोजना पर कार्य शुरू किया गया। प्रारंभिक तौर पर 10 संभागीय परिवहन कार्यालयों में पीपीपी मोड ऑटोमेटेड फिटनेस एवं सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। सुगम और सहज लोक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये परमिट जारी होने के बाद आरटीओ द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाने की दूरी को 25 किलोमीटर से बढ़ाकर 250 किलोमीटर कर दिया गया है। लोक परिवहन एवं वाणिज्यिक वाहनों में जीपीएस बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की जा रही है। पीयूसी सेंटर के लिए प्रदेश में एकीकृत वेब एप्लीकेशन की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए अन्य राज्यों में प्रदेश में संचालित व्यवस्था का अध्ययन कर उन संस्थाओं के प्रस्तुतीकरण का परीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में मैक्सी-कैब, मोटर कैब, आटो-रिक्शा और मोटर-साईकिल को भाड़े पर देने के लिए एक एग्रीगेटर पॉलिसी जारी की गई। विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शैक्षणिक वाहनों के लिए नियंत्रण एवं विनियमन योजना-2019 शुरू की गई। बैटरी चलित वाहनों पर एक समान चार प्रतिशत कर की नीति निर्धारित की गई। राज्य सरकार ने ग्वालियर व्यापार मेले में 2018-19 में गैर परिवहन यानों तथा छोटे परिवहन यानों को जीवनकाल-कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। एक अन्य आदेश के अनुसार बकाया राजस्व की वसूली के लिए ऐसे व्यावसायिक वाहनों के करों में छूट प्रदान की गई जिनकी आयु 5 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम हो, क्रमबद्ध तरीके से छूट दी गई।

■ मुकेश दुबे

साप्ताहिक
• साप्ताहिक 8 जनवरी 2019 से 14 जनवरी 2020
जालंधर ब्रीज
www.jalandharbreeze.com

डिजीटल इंडिया

चोरी हुए मोबाइल को तुरंत करा सकेंगे ब्लॉक, शुरू हुई नई सेवा

चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रेसिंग करने के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के शुरुआत के साथ ही अब ग्राहक अपने चोरी या खोए हुए मोबाइल की सूचना साझा कर उन्हें ब्लॉक करा सकते हैं। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने **इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर** नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें देश के सभी स्मार्टफोन और फीचर फोन के आईएमईआई नंबर दर्ज करने का काम चल रहा है। हेल्पलाइन नंबर 14422 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद आईएमईआई नंबर के इस्तेमाल से फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा और पोर्टल के माध्यम से पुलिस इसे ट्रैक कर सकेगी।

वॉट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म का एक वेब-फ्रेंडली वर्जन साल 2015 में लॉन्च किया था। वॉट्सएप वेब की मदद से यूजर्स को उनके डेस्कटॉप पर भी मेसेजिंग सर्विस इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिल गया है। इस वेब वर्जन में स्मार्टफोन एप पर मिलने वाले लगभग सारे फीचर्स दिए गए हैं, हालांकि वीडियो और वॉइस कॉलिंग का फीचर वॉट्सएप वेब पर यूजर्स को नहीं मिलता। वेब वर्जन पर मिलने वाले कई फीचर्स एप पर आपका एक्सपीरियंस बेहतर बना देते हैं। हम आपको ऐसे ही फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

Whatsap में आए चार खास फीचर्स

अभी करें ट्राई

एकसाथ दो अकाउंट करें इस्तेमाल

अगर आप गूगल क्रोम में वॉट्सएप वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एकसाथ दो अकाउंट्स चलाने का विकल्प भी मिल जाता है। पहला अकाउंट आप नॉर्मल मोड में चला सकते हैं और दूसरा अकाउंट आपको क्रोम एप के इनकॉग्निटो मोड में इस्तेमाल करना होगा। वॉट्सएप सिंगल ब्राउजर में केवल एक ही अकाउंट इस्तेमाल करने का विकल्प देता है, लेकिन इनकॉग्निटो मोड की मदद से दो अकाउंट एकसाथ चल पाएंगे।

टूलकिट एक्सटेंशन

अपने ब्राउजर में यह एक्सटेंशन इस्तेमाल करने के बाद आपको कई खास फीचर वॉट्सएप वेब के लिए मिल जाएंगे। बैकग्राउंड नोटिफिकेशन फीचर की मदद से आप बिना वॉट्सएप वेब टैब ओपन किए ही मेसेज पढ़ सकेंगे, और इसके लिए आपको केवल पॉइंटर एक्सटेंशन आइकन के ऊपर ले जाना होगा। साथ ही आप चैट बबल्स को स्ट्रेच भी कर सकेंगे, जो ऑप्शन अब तक एप में नहीं मिलता।

इमोजी शॉर्टकट

वॉट्सएप वेब पर एक पूरी तरह से नया इमोजी आइकन टेक्स्ट बार के साइड में मिलता है। इसपर क्लिक करते ही एप में मिलने वाले सारे इमोजी की लाइब्रेरी ओपन हो जाती है। हालांकि, बिना इमोजी ट्रे ओपन किए किसी इमोजी को ऐक्सेस करने का एक शॉर्टकट भी है। इसके लिए आपको कॉलन लगाकर केवल इमोजी रिएक्शन के पहले दो लेटर टाइप करने होंगे, इसके बाद इमोजी चैट में दिखने लगेगा। उदाहरण के लिए अगर आपको sad इमोजी भेजना है, तो :sa लिखना होगा।

पिक्चर-इन-पिक्चर मोड

आपने देखा होगा कि वॉट्सएप वेब पर आने वाले विडियो को देखने पर बड़ी विंडो खुलती थी जिसमें विडियो प्ले होता है। लेकिन इस फीचर के आने के बाद वॉट्सएप पर आने वाला विडियो अलग बॉक्स में खुल जाएगा, जिसकी फायदा यह होगा कि आप विडियो देखने के साथ-साथ चैटिंग भी कर सकेंगे। बता दें कि पहले यह फीचर सिर्फ वॉट्सएप पर शेयर किए गए विडियो के साथ ही काम करता था लेकिन अब इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियो का भी सपोर्ट दे दिया गया है।

Gmail में अनचाहे ईमेल से हैं परेशान?

इन 4 तरीकों से करें ब्लॉक

इंटरनेट की वजह से पिछले कुछ सालों में कम्यूनिकेशन का तरीका काफी बदल गया है। आजकल यूजर कनेक्ट रहने के लिए केवल फोन कॉल पर ही निर्भर नहीं है। इंस्टैंट मेसेजिंग के साथ ही कई विडियो कॉलिंग एप के आने से अब अपने फ्रेंड और फैमिली से कनेक्ट रहना काफी सुविधाजनक हो गया है। हालांकि, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एप्स के आने के बावजूद भी ईमेल ने अपनी जगह बनाई हुई है। ईमेल आजकल सर्विसेज में साइनअप, वेरिफिकेशन और कम्युनिकेशन के साथ ही कई दूसरी चीजों के लिए भी जरूरी हो गया है। कई वेबसाइट और एप अकाउंट क्रिएट करने के लिए ईमेल की ही मांग करते हैं।

ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में दुनियाभर में सबसे बड़ा नाम गूगल के Gmail का है। जीमेल एक टॉप की ईमेल सर्विस है जो यूजर्स को फ्री में ईमेल से जुड़े सारे काम करने की सहूलियत देती है। इसके साथ ही यह स्पैम ईमेल्स को भी पहचान लेता है। अगर आप एक रेग्युलर जीमेल यूजर हैं, तो आप स्पैम ईमेल से जरूर वाकिफ होंगे। जीमेल यूजर्स को स्पैम डिटेक्शन का फीचर देता है। वहीं, अगर आप स्पैम और फर्जी ईमेल के आने से काफी परेशान हैं, तो आप जीमेल पर इन ईमेल्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, लेकिन हम यहां आपको स्पैम और फर्जी ईमेल्स से बचने के चार बेस्ट तरीकों के बारे में बता रहे हैं।

किसी खास सेंडर को करें ब्लॉक

अगर आप किसी खास आईडी से आने वाले ईमेल्स से परेशान हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर उसे ब्लॉक कर सकते हैं-

- अपने जीमेल अकाउंट में साइन अप करें।
- उस ईमेल को सर्च करें जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं।
- 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करें।
- यहां दिए गए ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करें।

की वर्ड्स से करें ब्लॉक

अगर आप अकाउंट में ईमेल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कीवर्ड्स के जरिए ईमेल्स को ऑटोमैटिकली डिलीट या ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

- जीमेल अकाउंट में साइनअप करें।
- यहां आपको सर्च ईमेल ऑप्शन में दिए गए ट्राई एंगल आइकन (ड्रॉप डाउन मेन्यू) पर क्लिक करना है।
- यहां दिए गए बॉक्स में प्रमोशनल अनसब्सक्राइब जैसे कीवर्ड्स को टाइप करें।
- यहां क्रिएट फिल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट कर डायलॉग बॉक्स में दिए गए Delete it ऑप्शन पर क्लिक करें।

फिल्टर्स के जरिए करें ब्लॉक

अगर आप एक-एक कर सेंडर्स को ब्लॉक नहीं करना चाहते, तो इसके लिए फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

- जीमेल अकाउंट में साइन अप करें।
- यहां आपको सर्च ईमेल ऑप्शन में दिए गए ट्राईएंगल आइकन (ड्रॉप डाउन मेन्यू) पर क्लिक करना है।
- इस मेन्यू में आपको उन नामों और ईमेल आईडी को सर्च करना है जिन्हें आप ब्लॉक करना चाहते हैं।
- अब क्रिएट फिल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
- ऐसा करने के बाद डायलॉग बॉक्स में आए Delete it ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद दोबारा क्रिएट फिल्टर को सिलेक्ट करें।

जीमेल के अनसब्सक्राइब फीचर का करें इस्तेमाल

जीमेल अपने यूजर्स को अनसब्सक्राइब फीचर के जरिए अनचाहे ईमेल्स को ब्लॉक करने की सुविधा देता है। इस फीचर का इस्तेमाल ईमेल्स में नीचे दिए गए अनसब्सक्राइब लिंक से किया जा सकता है। जिस प्रमोशनल ईमेल को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसमें नीचे दिए अनसब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें। जीमेल उस ईमेल सेंडर को ब्लॉक से पहले आपसे कुछ सवाल पूछेगा।

जब स्लो हो इंटरनेट तो यूं ऑफलाइन करें ट्विटर का इस्तेमाल

भारत समेत दुनिया भर के यूजर्स को अक्सर इंटरनेट स्लोडाउन का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप अपने फेवरेट एप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हाल ही में NCR में इंटरनेट स्लो भी था। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने यह कंफर्म भी किया कि आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप इंटरनेट स्लोडाउन की स्थिति में भी ट्विटर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके ट्विटर अकाउंट से आपका नंबर लिंक होना चाहिए। आपको ट्विटर शॉर्ट कोड पता होना चाहिए।

- भारत में ट्विटर का शॉर्ट कोड 9248948837 है।
- ट्विटर के सपॉर्ट पेज से पता चलता है कि यूजर 9248948837 पर SMS भेजकर ट्विटर से मेसेज रिसीव कर सकेंगे।
- आप जो भी मेसेज भेजना चाहते हैं उसे टाइप कर 9248948837 पर सेंड कर सकते हैं।
- आपने जो भी मेसेज टाइप करके 9248948837 पर भेजेंगे वह ट्वीट आपकी ट्विटर प्रोफाइल पर पोस्ट हो जाएगा।

हाल ही में डाउन हुआ था ट्विटर

हाल ही में दुनिया भर में ट्विटर वेबसाइट डाउन हो गई थी। डाउन डिटेक्टर वेबसाइट के मुताबिक, भारत, यूएसए, स्पेन, यूके और जापान समेत कई देशों में ट्विटर 17 दिसंबर को कुछ वक्त के लिए डाउन हुआ था। हालांकि, बाद में फिर से साइट की सर्विसेज शुरू हो गई और प्लैटफॉर्म ठीक से काम कर रहा है। डाउन डिटेक्टर इंडिया वेबसाइट की ओर से कहा गया है कि ट्विटर पर मंगलवार शाम 8 बजकर 36 मिनट से कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। साइट ने यूजर्स से पूछा कि क्या उन्हें भी दिक्कते हुईं। 900 से ज्यादा यूजर्स ने 8 बजकर 30 मिनट पर इसे रिपोर्ट किया। बता दें, डाउन डिटेक्टर नजर रखता है कि इंटरनेट पर कोई वेबसाइट कितनी देर तक और कब डाउन हुई है।

नेटवर्क न हो तो भी ऐसे करें वॉयस कॉल

इन एप्स से कर सकते हैं वॉयस कॉल

Truecaller

व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के अलावा आप चाहें तो वॉयस कॉल करने के लिए टू कॉलर एप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू कॉलर एप की मदद से भी कई काम किए जा सकते हैं। वॉयस कॉल करने के लिए सबसे पहले टू कॉलर एप को खोलें और फिर उस व्यक्ति का नाम खोजें जिन्हें आप कॉल करना चाहते हैं। जिस भी व्यक्ति को आप कॉल मिलाना चाहते हैं उनकी प्रोफाइल में जाएं यहां आपको वॉयस कॉल के लिए बटन दिखाई देगा। वॉयस कॉल बटन पर क्लिक करते ही एप इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से आपकी कॉल को कनेक्ट कर देगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर बताए गए इन एप्स की मदद से केवल उस ही व्यक्ति को कॉल किया जाना संभव है जो व्यक्ति इन एप का इस्तेमाल कर रहा हो।

टेक जगत से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी जानने को उत्सुक रहते हैं तो हमारा आज का यह लेख खास आप लोगों के लिए है। आज हम अपने लेख के माध्यम आपको ऐसे एप्स के बारे में जानकारी मुहैया कराएंगे, जिनकी मदद से आप मोबाइल में नेटवर्क ना होने की स्थिति में भी वॉयस कॉल कर पाएंगे। एक बात जो गौर करने वाली है वह यह है कि इन एप्स की मदद से वॉयस कॉल करना तभी संभव हो पाएगा, जब आपको स्मार्टफोन वाई-फाई से कनेक्ट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एप्स इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से आपके कॉल को कनेक्ट करते हैं। इनमें से ज्यादातर एप्स का इस्तेमाल हम रोज करते हैं तो आइए अब आपको इन एप्स के बारे में जानकारी मुहैया कराते हैं-

WhatsApp

सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक के इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप एक बेहद ही पॉपुलर एप है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एप की मदद से केवल चैट ही नहीं, बल्कि मीडिया फाइल को शेयर करना, वॉयस और वीडियो कॉल आदि कई काम किए जा सकते हैं। यदि आपके फोन में किसी कारण से मोबाइल नेटवर्क नहीं है लेकिन आप वाई-फाई से कनेक्टेड हैं तो आप वॉयस कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप एप को खोलें। इसके बाद आप जिस भी व्यक्ति को कॉल मिलाना चाहते हैं उसके नाम पर क्लिक करें। नाम पर क्लिक करने के बाद चैट विंडो खुल जाएगी यहां आपको ऊपर दाहिनी ओर वॉयस और वीडियो कॉल का आइकन बना नजर आएगा। वॉयस कॉल बटन पर क्लिक कर आपका कॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से कनेक्ट हो जाएगा।

Facebook Messenger

फेसबुक का मैसेंजर एप केवल चैट करने के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य कामों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है जैसे कि वॉयस कॉल करना और फेसबुक पर स्टेटस पोस्ट करना। व्हाट्सएप की तरह ही फेसबुक मैसेंजर में आप जिस व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं उसके नाम पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद चैट विंडो खुल जाएगी और यहां आपको व्हाट्सएप एप की तरह ही ऊपर दाहिनी ओर दो बटन दिखाई देंगे। एक वॉयस और दूसरा वीडियो कॉल करने के लिए। वॉयस कॉल बटन पर क्लिक करते ही इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा।

इन 29 एप्स को अभी कर दें Delete

ये खतरनाक एप्स आपके पर्सनल डाटा और लोकेशन को कर रही रिकॉर्ड

गूगल ने इस साल करीब 1000 से ज्यादा वायरस एप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। इनमें से कुछ ऐडवेयर थी, कुछ एप्स मैलवेयर के रूप में स्पॉट की गई। जानकारी के मुताबिक कुछ एप्स में तो ऐसी खामी पाई गई कि वह यूजर्स को बिना बताए उनकी बातें और लोकेशन दोनों को रिकॉर्ड कर रही थीं। हालांकि इन एप्स में 29 एप्स सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में पाई गईं। यह ऐसी एप्स हैं जो यूजर्स के फोन से उनकी फोटोज चोरी कर रही हैं। वैसे तो इन एप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, मगर जिन फोन में यह अभी भी इंस्टॉल्ड है, उनके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं उन 29 एप्स की लिस्ट, ताकि इनमें से कोई भी अगर आपके फोन में हो तो उसे तुरंत डिलीट कर दें।

इस लिस्ट में ये एप्स कुछ इस प्रकार हैं

1.	सेल्फी कैमरा प्रो
2.	प्रो कैमरा ब्यूटी
3.	प्रिज्मा फोटो इफेक्ट
4.	फोटो एडिटर
5.	फोटो आर्ट इफेक्ट
6.	हॉरिजन ब्यूटी कैमरा
7.	कार्टून फोटो फिल्टर,
8.	कार्टून इफेक्ट,
9.	कार्टून आर्ट फोटोज,
10.	कार्टून आर्ट फोटो
11.	कार्टून आर्ट फोटो फिल्टर
12.	ऑसम कार्टून आर्ट
13.	आर्टफ्लिप फोटो एडिटिंग
14.	आर्ट फिल्टर
15.	आर्ट फिल्टर फोटो
16.	आर्ट फिल्टर फोटो इफेक्ट्स
17.	आर्ट फिल्टर फोटो एडिटर
18.	आर्ट एडिटर
19.	वॉलपेपर एचडी
20.	सुपर कैमरा
21.	पिक्सचर
22.	मैजिक आर्ट
23.	फिल आर्ट फोटो एडिटर
24.	इमोजी कैमरा
25.	ब्यूटी कैमरा
26.	आर्टिस्टिक इफेक्ट फिल्टर
27.	आर्ट इफेक्ट फिल्टर
28.	आर्ट इफेक्ट
29.	फिल्टर फोटो एडिटर

RBI ने मनी मोबाइल एप किया लॉन्च

अब नकली नोट की पहचान करना होगा आसान

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने नेत्रहीन लोगों के लिए एक खास मोबाइल एप मनी (Mobile Aided Note Identifier) को लॉन्च कर दिया है। इस एप की मदद से लोग आसानी से नकली नोट की पहचान कर सकेंगे। आरबीआई का यह एप नोट की जांच कर बताएगा कि नोट कितने का है और असली है या नहीं। वहीं, लोग इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप की खासियत है कि यह नोट की पहचान अच्छे से करता है और जरूरी जानकारी साउंड के जरिए देता है। तो चलिए जानते हैं आरबीआई के एप के बारे में...

Mobile Aided Note Identifier एप की खूबियां

- आरबीआई का एप अपने यूजर्स को नोट की सटीक जानकारी देता है। इसके अलावा यूजर्स को इस एप में ऑडियो सेंसर का सपोर्ट मिलेगा, जिससे वह इसको अपनी आवाज से कंट्रोल कर सकेंगे।
- अगर नोट कहीं से मुड़ा है, तो भी यह एप उसकी आसानी से पहचान कर सकेगा।
- मनी एप इंटैग्लियो प्रिंटिंग, टैक्सटाइल मार्क, साइज, नंबर, रंग और मोनोक्रोमेटिक पैटर्न की आसानी से जांच करता है।

गूगल लाया नया फीचर पासवर्ड चेकअप

कितने सेफ हैं आपके जरूरी अकाउंट

Password का चुटकियों में चल जाएगा पता

गूगल ने अपने पासवर्ड मैनेजर में नया फीचर (Password checkup) जोड़ दिया है। इस नए फीचर को यूजर्स की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए पेश किया गया है, जहां से यूजर्स चेक कर पाएंगे कि उनका पासवर्ड किसी बड़े सिक्योरिटी ब्रीच का हिस्सा तो नहीं है। हालांकि यह गूगल का पासवर्ड चेकअप पहले भी एक्सटेंशन के तौर पर मौजूद था, लेकिन अब गूगल इसे सीधा गूगल अकाउंट में दे रही है। यूजर्स password.google.com में जाकर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।

ऐसे चेक होगा आप सेफ पासवर्ड यूज कर रहे हैं या नहीं

इसमे यूजर के लॉगइन की जानकारियों को उन करोड़ो अकाउंट्स से मिलाया जाएगा, जिनपर सिक्योरिटी का खतरा है। अगर किसी बड़ी हैकिंग में आपका अकाउंट पासवर्ड ब्रीच हुआ है तो गूगल आपको पासवर्ड बदलने का सलाह देगा। अगर आप कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको गूगल अगाह करेगा। गूगल ने एक बयान में कहा है कि 'पासवर्ड चेकअप आपकी जानकारी गूगल को भेजता है, जिससे सिक्योरिटी चेक की जाती है, लेकिन यूजर्स का डेटा इनक्रिप्टेड और और उसे कोई भी नहीं देख सकता है। गूगल ने कहा कि यूजर्स के पासवर्ड हमारे पास हैश (#) साइन में हैं और इनक्रिप्टेड हैं। जानकारी के लिए बता दें कि गूगल ने इसी साल फरवरी में अपने वेब ब्राउजर क्रोम के लिए पासवर्ड चेकअप एक्स्टेंशन लॉन्च किया था। कंपनी के मुताबिक यह एक्स्टेंशन शुरुआत में ही 10 लाख बार डाउनलोड किया गया था।

अमेजन फायर टीवी पर आया एप्पल टीवी एप

ऐसे करें डाउनलोड

वीडियो स्ट्रीमिंग बाजार में एप्पल और अमेजन भले ही एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी कंपनी हों, लेकिन अब आप एप्पल टीवी एप को अमेजन फायर स्टिक पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल टीवी वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा में उपयोगकर्ताओं को सभी समान सेवाएं मिलेंगी जो उन्हें एप्पल टीवी सेट-टॉप बॉक्स से मिलती है। इससे उपभोक्ता न केवल नए टीवी शो पाएंगे बल्कि अपने मौजूदा आईट्यून्स मीडिया लाइब्रेरी से फिल्मों और शो को भी खरीद भी सकते हैं। वहीं कुछ समय के लिए रेंट पर भी ले सकते हैं। इस एप को हाल ही में सैमसंग स्मार्ट टीवी के साथ-साथ रोकू उपकरणों पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेजन के फायर टीवी स्टिक (2जीन) और फायर टीवी स्टिक 4के को भारत समेत दुनिया भर में लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

एप्पल टीवी एप ऐसे करें डाउनलोड

इसके लिए आप फायर टीवी स्टिक ओनर एप सेक्शन में जाकर Apple TV एप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार जब आप एप्पल टीवी एप डाउनलोड कर लेते हैं, तब इसे इंस्टॉल करने के लिए गेट बटन पर क्लिक करें। आप अमेजन वेबसाइट पर सीधे एप्पल टीवी एप की सूची में भी जा सकते हैं और एप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन उपयोगकर्ताओं के पास एलेक्सा-सक्षम वॉयस रिमोट है, वे अपने उपकरणों को एप्पल टीवी एप ढूंढने के लिए भी कह सकते हैं। एप्पल टीवी+ की सदस्यता के लिए भी एप्पल डिवाइस की आवश्यकता होगी।

ये मिलेगा फायदा

यह भारत में 99 रुपए प्रति माह शुल्क में उपलब्ध होगा। इसके साथ सात दिवसीय निःशुल्क परीक्षण की सुविधा मिलेगी। एक सदस्य की मैंबरशिप का उपयोग परिवार के छह लोगों द्वारा किया जा सकता है। जिस उपभोक्ताओं ने 10 सितंबर के बाद नया आईफोन, आईपैड, मैक, आईपॉड टच या एप्पल टीवी खरीदा है, वह एक साल की मुफ्त सदस्यता के लिए पात्र होंगे।

सिखों की सुरक्षा संबंधी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा टिप्पणी चिंताजनक-कैप्टन अमरिन्दर सिंह

अकाली दल को केंद्र में सत्ताधारी गठजोड़ से नाता तोड़ने के लिए कहा

■ चंडीगढ़/विजय कुमार

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा भारत में सिखों के महफूज़ न होने संबंधी की गई टिप्पणी पर गहरी चिंता ज़ाहिर करते हुए जत्थेदार साहिब से अपील की कि उनकी तरफ से अकालियों पर केंद्र के सत्ताधारी गठजोड़ के साथ अपने सभी नाते तोड़ने के लिए दबाव डाला जाये क्योंकि मुल्क में अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा की भावना को यकीनी बनाने में केंद्र सरकार नाकाम रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे वह खुद श्री अकाल तखूत साहिब के जत्थेदार साहिब के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं हैं परन्तु यदि वह इस बात को महसूस करते हैं तो उनको यह मामला शिरोमणि अकाली दल के पास उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जत्थेदार साहिब अकालियों को केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से गठजोड़ का सम्बन्ध तोड़ने के लिए कहें।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के उलट भारत को हमेशा ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का गर्व रहा है और यहाँ धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सिखों के मन में यह भावना पाई जा रही है कि वह यहाँ सुरक्षित नहीं हैं तो यह बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यदि इस मुल्क में सिख अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जैसे कि श्री अकाल तखूत साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है, तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है जिसको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली अपने आप को सिख धर्म और भाईचारे के हितों के रखवाले होने का दावा करते हैं तो इनको इस मसले पर स्टैंड लेना चाहिए और अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल को तुरंत केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफ़ा देने के लिए कहना चाहिए। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इधर-उधर घटती कुछ घटनाओं से चाहे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं हैं परन्तु धारणा का महत्व भी हकीकत जितना ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में सिख बहुत काले दौर में से गुज़रे हैं और इस तरह का कोई भी एहसास उनमें फिर डर की भावना पैदा करेगा जो भाईचारे के हितों के साथ-साथ मुल्क के लिए घातक सिद्ध होगा। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि सिखों के बहुसंख्यक वाले राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने हमेशा इस बात को यकीनी बनाया है कि न सिर्फ़ पंजाब में बल्कि अन्य राज्यों में भी भाईचारे के हितों की रक्षा की जाये। उन्होंने जहाँ कहीं भी सिखों को कोई दुख-तकलीफ़ पहुँची तो उन मामलों में दिए निजी दखल को भी याद किया।

नागरिकता संशोधन एक्ट के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल की पाखंडबाज़ी का ज़िक्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अकालियों को कहा कि वह ऐसे मामलों पर दोहरे खेल खेलने की बजाय भारत में अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामलों पर स्पष्ट स्टैंड लें। उन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है कि उनको यह एहसास हुआ है कि वह केंद्र में गठजोड़ का हिस्सा बने रहना जारी नहीं रख सकते क्योंकि केंद्र सरकार मुल्क में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रही है परन्तु फिर भी इन अल्पसंख्यकों के रक्षक होने का दावा करते हैं।

जालन्धर विकास अथारटी योजनाबद्ध और भविष्य मुखी विकास की तरफ विशेष ध्यान दें-डिप्टी कमिश्नर

गैर कानूनी कलोनियों और मैरिज पेलैसों के विरुद्ध कड़ी कार्यावाही के आदेश

■ जालन्धर/नीरज

डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने जालंधर विकास अथारटी के आधिकारियों को कहा है कि वह शहर के योजनाबद्ध और भविष्य मुखी विकास की तरफ विशेष ध्यान दें। आज यहाँ अथारटी के आधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिशनर ने कहा कि विकास के लिए सूक्ष्म योजनाबंदी की तरफ ध्यान दिया जाये और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की सेवाओं को लेकर भविष्य संबंधी प्रोजैक्ट बनाये जाये जिससे लोगों को आने वाले लंबे समय तक अच्छी सेवाएं दीं जा सकें। विकास कार्यों में योजनाबंदी में पार्दशता को सब से बड़ी ज़रूरत बताते हुए उन्होने कहा कि अथारटी का मुख्य उदेश्य जिले का संपूर्ण विकास है जिस के लिए जहाँ योजनाबंदी अहम है वहीं ग़ैर कानूनी तौर पर बनाये जाने वाले किसी भी ढांचे, कालोनी के विरुद्ध सखूत कार्यवाही अमल में लाई जाये। उन्होने कहा कि शहर में और इस के आस-पास बनाई जा रही कलोनियों की लगातार पड़ताल की जाये और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यावाही की जाये।

डिप्टी कमिशनर ने यह भी कहा कि रिहायशी क्षेत्रों में प्राथमिक सुविधा लोगों तक आसानी से पहुँचने को विश्वसनीय बनाया जाये। उन्होने कहा कि ग़ैर कानूनी तौर पर चल रहे मैरिज पेलैसों के विरुद्ध योग्य कार्यवाही की जाये।

डिप्टी कमिशनर ने विकास अथारटी को यह भी निर्देश दिए कि उनके अधीन आने वोल क्षेत्रों में खाली पड़े स्थानों की रिहायशी और व्यापारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए उचित प्रयोग की जाये।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य प्रशासक जे.डी.ए. बरजिन्दर सिंह, एस.डी.एम. डा.जय इन्द्र सिंह और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

जनता ने बार बार लोकतांत्रिक जनादेश देकर नरेन्द्र मोदी की जन स्वीकृति को स्पष्ट किया : अमित शाह

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र के अंदर शासन की सफलता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जन स्वीकृति और जनता का आशीर्वाद होता है तथा जनता ने बार-बार नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लोकत्रांत्रिक जनादेश देकर इस जन स्वीकृति को स्पष्ट किया है। अमित शाह ने यहां कर्मयोगी ग्रंथ के अनावरण के अवसर पर कहा, ''अब तक घोषणा पत्र केवल एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाते थे । लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हमारा 2014 का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिये, भाजपा 90 प्रतिशत कार्य पूरे कर चुकी है।'' पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर परोक्ष निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित मुद्दों को छूते हुए सब लोग डरते थें, चाहे वो अनुच्छेद 370, 35ए हो, शरणार्थियों को नागरिकता और राम जन्मभूमि पर स्पष्ट रूख लेने का मामला हो या तीन तलाक का मुद्दा हो। शाह ने कहा, '' मोदी जी ने आज देश में 70-70 साल से लंबित समस्याओं को समाप्त करने का काम किया है।'' उन्होंने कहा कि साल 1967 से लेकर 2014 तक हमारे देश की राजनीति को तीन नासूरों तुष्टिकरण, जातिवाद और परिवारवाद ने काफी क्षति पहुंचाई । मोदी जी ने 2014 के बाद इन तीनों नासूरों को समाप्त करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की विदेश नीति को एक लंबे समय के बाद गढ़ने का काम भी मोदी जी ने किया है। समानता के आधार पर विदेश नीति को लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी भूटान जाते हैं तो बड़े भाई का व्यवहार नहीं करते और जब अमेरिका जाते हैं तो आंख में आंख डालकर बात करने का साहस नरेन्द्र मोदी ने ही किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने विदेश नीति और सुरक्षा नीति के घालमेल को समाप्त करने का काम किया है। शाह ने कहा कि 2014 से पहले इस देश की कोई सुरक्षा नीति ही नहीं थी, विदेश नीति ही सुरक्षा नीति पर हावी हो गयी थी। नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि हम पर कोई हमला करेगा तो उसे सीधा जवाब दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम 40 प्रतिशत बजट का हिस्सा राज्यों को देने का काम किया गया जो पहले 30 प्रतिशत था।

इस प्रकार से संघवाद को मजबूत बनाने का काम किया गया। शाह ने इस संबंध में उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय एवं स्वच्छता योजना सहित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। भाजपा अध्यक्ष ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी के कामकाज का जिक्र किया और कहा कि बहुत ही कठिन समय में दायित्व संभालने के बाद उन्होंने गुजरात सर्वस्पर्शी एवं सर्व समावेशी शासन के मॉडल के रूप में स्थापित करने का काम किया।

राष्ट्रपति कोविंद की दरियादिली, दुल्हन को नहीं बदलना पड़ा अपना वेन्यू, जानें पूरा मामला

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद एक विदेशी दुल्हल की मंगलवार को केरल के पांच सितारा होटल ताज विवांता में होगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति कार्यालय ने सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रपति के होटल में ठहरने के दौरान उसी होटल में हो रही विदेशी दुल्हन की शादी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। दरअसल, विदेशी दुल्हन की शादी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा एक ही दिन होने की वजह से सुरक्षा अधिकारियों ने दुल्हन के परिवारवालों से अनुरोध किया था कि वह अपना वेन्यू कहीं और शिफ्ट कर लें। जिसकी वजह से दुल्हन का परिवार चिंतित हो गया कि इतने कम समय में ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद दुल्हन एश्ले ने राष्ट्रपति कार्यालय को ट्विटर पर टैग करते हुए अपनी व्यथा सुनाई और मदद की गुहार लगाई। दुल्हन एश्ले ने ट्वीट किया ही था कि राष्ट्रपति कोविंद ने उन्हें आश्वासन दिया कि हमारे ठहरने की वजह से आपकी शादी में कोई व्यवधान नहीं होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलहाल लक्षद्वीप दौरे पर हैं। लक्षद्वीप दौर पर जाने से पहले सोमवार की रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोच्चि के पांच सितारा होटल ताज विवांता में गुजारी और फिर मंगलवार सुबह तकरीबन साढ़े नौ बजे वह लक्षद्वीप के लिए रवाना हो गए।

दुल्हन एश्ले ने क्या कहा था ?

दुल्हन एश्ले ने राष्ट्रपति कार्यालय को टैग करते हुए लिखा कि सुरक्षा अधिकारियों ने 48 घंटे पहले हमें अपना मैरिज वेन्यू बदलने के लिए कहा। यह हमारे से आसान नहीं है। फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद से महिला काफी खुश नजर आ रही है।

लोक कल्याण स्कीमों का लाभ लोगों तक पहुँचाने को विश्वसनीय बनाया जाये -सोनी

कैबनिट मंत्री की तरफ से जिला शिकायत निवारण समिति की मीटिंग की अध्यक्षता

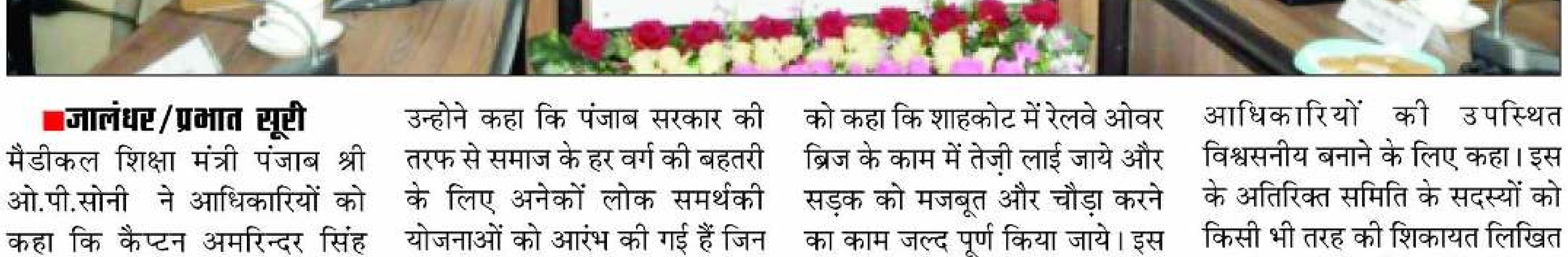

■ जालंधर/प्रभात सूरी

मैडीकल शिक्षा मंत्री पंजाब श्री ओ.पी.सोनी ने आधिकारियों को कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के नेतृत्व वाली सरकार के लोक कल्याण स्कीमों का लाभ निचले स्तर तक लोगों को पहुँचाने को विश्वसनीय बनाया जाये जिससे कमज़ोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को भी ऊँचा उठाया जा सके।

जिला प्रशासकी कंपलैक्स में जिला शिकायत निवारण समिति की मीटिंग जिस में श्री सोनी के साथ डिप्टी कमिशनर वरिन्दर कुमार शर्मा, पुलिस कमिशनर गुरप्रीत सिंह भुल्लर और एस.एस.पी. नवजोत सिंह माहल भी उपस्थित थे, उन्होने कहा कि राज्य सरकार की लोक कल्याण स्कीमों को लागू करने के लिए अधिकारी पाबंद हैं। उन्होने कहा कि सरकार की लोक कल्याण स्कीमों का लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए उच्च अधिकारी निजी तौर पर प्रयास करें और हर विभाग अपने से सबंधित लाभपात्रियों तक सीधी पहुँच करे। उन्होने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से समाज के हर वर्ग की बहतरी के लिए अनेकों लोक समर्थकी योजनाओं को आरंभ की गई हैं जिन का उदेश्य आम लोगों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है।

उन्होने कहा कि विकास योजनाओं और विशेष करके लोक कल्याण की स्कीमों को पूर्ण रूप में लागू करने के लिए वह हर महीने के पहले सप्ताह रिविऊ मीटिंग किया करेंगे जिससे इनकी प्रगति का लगातार जायजा लिया जा सके। मीटिंग के दौरान श्री सोनी ने पुलिस और नगर निगम को कहा कि वह शहर में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए संयुक्त योजनाबंदी करके उसे ज़मीनी स्तर पर लागू करें।

इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग को आदमपुर शहर में फ्लाई ओवर के निर्माण शीघ्र पूर्ण करने के आदेश भी दिया गया, इसके अतिरिक्त लंबा गाँव से जंडूसिंगा रोड को भी 30 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

कैबिनेट मंत्री ने आधिकारियों को कहा कि शाहकोट में रेलवे ओवर ब्रिज के काम में तेज़ी लाई जाये और सड़क को मजबूत और चौड़ा करने का काम जल्द पूर्ण किया जाये। इस के अतिरिक्त उन्होने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को कहा कि वह खुरला किंगरा में कम्यूनटी स्वास्थ्य केंद्र को चालू करने की संभावनाओं तलाशना, इस के अतिरिक्त फिल्लौर से नकोदर रोड और सांई मंदिर से मिट्ठापुर चौक तक सड़क के निर्माण का काम पूर्ण करने के लिए लोक निर्माण और नगर निगम के आधिकारियों को जरुरी निर्देश जारी किये गए। उन्होंने यह भी बताया कि न्यू ग्रीन माडल टाऊन रोड पर 48.88 लाख रुपए की लागत से काम जल्द शुरू किया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने मीटिंग के दौरान यह भी कहा कि सभी सबंधित सदस्यों को मीटिंग का एजेंडा आगामी ही दिया जाये जिससे सभी मुद्दों पर खुल कर विचार चर्चा हो सके।

इस तरह उन्होने मीटिंग के दौरान सबंधित विभागों के सभी उच्च आधिकारियों की उपस्थित विश्वसनीय बनाने के लिए कहा। इस के अतिरिक्त समिति के सदस्यों को किसी भी तरह की शिकायत लिखित रूप में पहला के तौर पर देने के लिए कहा गया जिससे मीटिंग के दौरान उसका निपटारा किया जा सके। उन्होने जालंधर जिले में लोगों के कल्याण के लिए उठाये जा रहे कदमों के लिए जिला प्रशासन की कार्यावाही की प्रशंसा की।

इस अवसर पर विधायक रजिन्दर बेरी, हरदेव सिंह लाडी शोरोवालिया, मेयर जगदीश राज राजा, कमिशनर नगर निगम दीपरवा लाकड़ा, अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर जसबीर सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर पुलिस गगनेश कुमार, एस.डी.एमज़ अमित कुमार, राहुल सिंधु, संजीव शर्मा, डा.जय इंद्र सिंह, विनीत कुमार, सचिव आर. ई. ए.डा.नयन, सिविल सर्जन डा.गुरिन्दर कौर चावला, डिप्टी डायरैक्टर सैनिक कल्याण मेजर (रिटा.) यशपाल, सहायक कमिशनर शायरी मल्होत्रा उपस्थित थे।

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING | DESIGN | TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

IELTS • PTE • TOEFL
SPOKEN ENGLISH

TOURIST VISA | STUDY VISA | PR
WORK PERMIT | HOLIDAY PACKAGES

CANADA AUSTRALIA USA U.K SINGAPORE EUROPE

9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal.
HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com
Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin